



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सेवा ही संकल्प,
राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा... 75 वर्ष

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर

गुरुव्यग्रंथी भजनलाल शर्मा
विकास पथ पर
आपणो अग्रणी राजस्थान...

2800 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना सहित

राजस्थान को 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए की परमाणु विद्युत, अक्षय ऊर्जा, रेल, सड़क, पेयजल, सिंचाई, सीवरेज, स्वास्थ्य एवं अन्य परियोजनाओं का उपहार

15 हजार युवाओं को

सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्रों का वितरण

मुख्य अतिथि

नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर

से नई ट्रेनों की शुरुआत

शिलान्यास

- बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना (8,500 करोड़ रुपए)
- जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर व बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें (13,183 करोड़ रुपए)
- राजसमन्द, झूंगरपुर, चितौड़गढ़, अजमेर, टोंक, जयपुर, भरतपुर, अलवर जिलों में जल संसाधन में रामजल सेतु परियोजना के 9 कार्य (18,468 करोड़ रुपए)
- बांसवाड़ा, उदयपुर, झूंगरपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं (5,884 करोड़ रुपए)
- भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण तथा 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण (878 करोड़ रुपए)
- बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में 220 केवी जीएसएस व लाइन निर्माण (348 करोड़ रुपए)

लोकार्पण

- 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं एवं 925 मेगावाट का नोख सोलर पार्क, फलौदी (10710 करोड़ रुपए)
- पीएम कुसुम-सी के तहत 895 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र (3,132 करोड़ रुपए)
- ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसानाला एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य (2,365 करोड़ रुपए)
- बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, झूंगरपुर, भर्तृहरि नगर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य (1,758 करोड़ रुपए)
- बाड़मेर जिले में 220 केवी जीएसएस व लाइन निर्माण (142 करोड़ रुपए)
- डीडवाना-कुचामन में सीवरेज एवं झुंझुनूं में सीवरेज व जल प्रदाय परियोजना का कार्य (226 करोड़ रुपए)
- आई.टी.डब्ल्यू.एण्ड.ई-गवर्नेंस सेन्टर (140 करोड़ रुपए)
- भरतपुर में आरबीएम चिकित्सालय में 250 बैडेड अस्पताल (128 करोड़ रुपए)

गरिमामयी उपस्थिति

हरिभाऊ किसनराव बागडे

माननीय राज्यपाल, राजस्थान

भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

प्रह्लाद जोशी

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

डी.डी. न्यूज़ पर लाइव प्रसारण



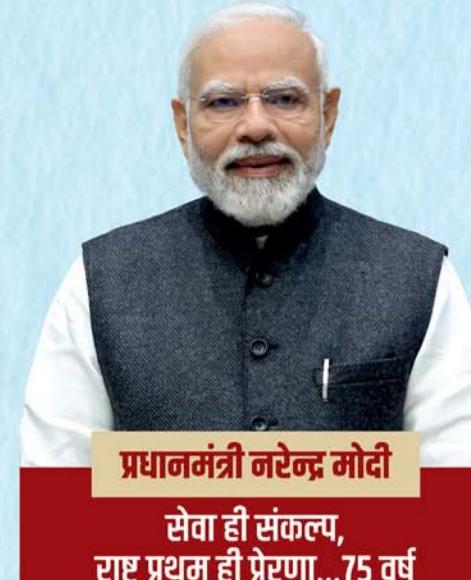
गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025 | दोपहर 12:00 बजे | नापला, छोटी सरवन (बांसवाड़ा)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान



भजन लाल शर्मा

मुख्यमंत्री, राजस्थान



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सेवा ही संकल्प,
राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा... 75 वर्ष

विकास के नए शिखर पर राजस्थान

₹1,22,000 करोड़ से अधिक की

परमाणु, अक्षय ऊर्जा, बिजली, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी
परियोजनाओं का उपहार

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

के द्वारा



गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025



13:00 बजे



बाँसवाड़ा, राजस्थान

केन्द्र सरकार की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं

शिलान्यास

अश्वनी माही बाँसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना
1-4 (4x700 MW)

590 MW एफडीआरई परियोजना (1560 MWp सौर
तथा 2500 MWh बीईएसएस), बीकानेर (अवाडा)

पावरग्रिड की तीन पारेषण योजनाएँ, राजस्थान से मध्य प्रदेश,
हरियाणा और पंजाब तक 15.5 GW अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु

300 MW सौर पीवी परियोजना, रामगिरि, आंध्र प्रदेश (सेकी)

उद्घाटन

- 925 MW नोख सौर पार्क, फलोदी, राजस्थान (आरएसडीसीएल)
- 400 MW सौर पावर परियोजना (जेएसडब्ल्यू एनर्जी)
- 300 MW सौर परियोजना (ईडन रिन्यूएबल्स)
- 200 MW सौर परियोजना (सनफ्री एनर्जी)

200 MW सौर परियोजना, बड़नू, राजस्थान (अवाडा)

300 MW सौर परियोजना (एसीएमई सोलर)

पीएम-कुसुम घटक-सी (फीडर स्तर सोलराइजेशन) के अंतर्गत⁺
विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र - राजस्थान (895 MW),
महाराष्ट्र (2458 MW), मध्य प्रदेश (99 MW), कर्नाटक (65 MW)

राजस्थान सरकार की विकास परियोजनाएं

जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, ऊर्जा,
स्थानीय स्वायत्त शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, तथा चिकित्सा
शिक्षा विभाग से संबंधित 31 कार्यों का शिलान्यास एवं 17 कार्यों का उद्घाटन
15,000 युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरण

हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ

- बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
- जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
- उदयपुर सिटी - चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन

परियोजना के लाभ

लोगों और उद्योगों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ परमाणु ऊर्जा का उत्पादन
जीवन को बेहतर बनाने और व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर हरित ऊर्जा की उपलब्धता
कृषि के लिए किफायती, विश्वसनीय और सतत सिंचाई ऊर्जा हुई सुनिश्चित
लोगों, स्थानीय व्यवसायों, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों के लिए बेहतर रेल संरक्ष
आर्थिक विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राजस्थान राज्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर
स्थानीय समुदायों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन

गरिमामयी उपस्थिति

श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े
राज्यपाल, राजस्थान

श्री भजन लाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री मनोहर लाल
केंद्रीय आवासन और शहरी
कार्य एवं विद्युत मंत्री

श्री प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय उपमोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक
वितरण; तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

श्री अश्वनी वैष्णव
केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री भूपेन्द्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण,
जन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

डॉ. जितेन्द्र सिंह

केंद्रीय राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान
(स्वतंत्र प्रभार) और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन
परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग

श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय, कानून एवं न्याय
(स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

श्री भागीरथ चौधरी
केंद्रीय कृषि एवं
किसान कल्याण राज्य मंत्री

श्रीमती दिया कुमारी
उप मुख्यमंत्री, राजस्थान

डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा

उप मुख्यमंत्री, राजस्थान

संपादकीय

विचार बिन्दु

जिस प्रकार जल कमल के पते पर नहीं ठहरता है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा के कर्म उससे नहीं चिपकते हैं। - छांदोग्य उपनिषद

राजस्थान में शहरीकरण: जल संरक्षण के मूलभूत प्रयास

रा

जस्थान भौतिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु प्राकृतिक जल संसाधनों के माले में यह सदैव पिछड़ा रहा है। यह की मूलस्थलीय जलवाय, कम वर्षा, भूजल का लगातार दोहन और जनसंख्या वृद्धि ने जल संकट को और गर्वा बना दिया है। हाल के वर्षों में शहरीकरण की तेज रफ्तार ने इस समस्या को अप्रूपी स्तर पर पहुंचा दिया है। गर्वों से शहरों की ओर पलायन, औद्योगिक बढ़ावों की स्थापना, बढ़ती आवासीय औलोगिक और जीवनशैली में बदलाव ने जल संसाधनों पर जरूरत दबाव डाला है। इस परिस्थिति में राजस्थान के शहरीकरण और जल संकट को संबंध घटाया से खाली करने के लिए संबंधित करती रही है।

राजस्थान के जल संकट की जड़ें इसकी भौतिक एवं जलवाय स्थितियों में छिपी हैं। यहां औसत 550 मिमी वर्षा होती है, जो देश के अन्य हिस्सों की जलवाय में बहुत कम है। पश्चिमी राजस्थान में यह और भी कम होके 200 मिमी के आसपास रहे जाते हैं। यहां मस्तिष्कल का विशेष श्वेतफल और रेत की दीनों के बीच बरी स्थितियां के अधिक में हमेशा से ही पानी के लिए संबंधित करती रही हैं। ऐसे में जब शहरीकरण तेजी से बढ़ा, तब जल संकट और जल जटिल हो गया।

शहरीकरण का प्रभाव सबसे पहले शहरों की पेयजल आपूर्ति पर दिखाई देता है। यजपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर जैसे शहरों की आवादी पिछड़ी दो दशकों में कई गुण बढ़ गई हैं। जोधपुर और बीकानेर जैसे शुक्र शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए नहीं और जल संकट की ओर वर्षा गर्वों में हालांकि बढ़ा जाते हैं। बाहर तो अस्थिति इनमें यहां से ही जल वितरण को लेकर और संबंधित बढ़ा देते हैं। यहां प्रासांगिक समाज और राष्ट्र के पुनर्विमर्श में अप्रत्याशित होती है।

इसके अलावा शहरीकरण ने भूजल देने को भी अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। परिस्थिति वर्षावरुप राजस्थान के अनेक शहरों में भूजल का स्तर 500 फॉट से भी नीचे चला गया। भूजल स्तर में लगावना परिवर्तन और एक योग्य वर्षा की ओर खर्च होता है। भूजल स्तर में लगावना परिवर्तन और रेत के लिए नहीं आवश्यक तरीका है। बल्कि कुछ और पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

औद्योगिक कार्यों पर जल संकट को बढ़ावा लाना एक बड़ा कारक है। शहरीकरण के साथ ही राजस्थान के अनेक शहरों में सेमेंट, वस्त्र, रसायन और खनन आधारित उद्योग स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों को बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता होती है। कई बार उद्योग बिना अनुमति के भूमित जल का दोहन करते हैं, जिससे आम जलात के लिए एपानी की उपलब्धता प्रभावित होती है। इसके साथ ही औद्योगिक अपर्याप्त जल का प्रदूषण जल स्रोतों को भी असुरक्षित बना देता है।

जल संकट के बढ़ावा के लिए जल संकट को केवल मात्रा के स्तर पर भी बढ़ावा है, बल्कि गुणवत्ता के स्तर पर भी बढ़ावा है। बहती आवादी और औद्योगिक गतिविधियों ने नालों और जलशायों को प्रभावित कर दिया है। अजमेर और उदयपुर जल संचयन, तालाबों और बावड़ियों का नई संबंधित की ओर खर्च होता है।

शहरीकरण जे जल संकट को केवल मात्रा के स्तर पर भी बढ़ावा है, जिसे शम्भव और वर्षा की ओर खर्च होता है। उदयपुर में यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपानी की उपलब्धता प्रभावित होती है। इसके बाद उदयपुर की जलवाय के लिए एपानी की उपलब्धता प्रभावित होती है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। जब शहरों में पानी की कमी होती है, तो गर्व और मध्यम वर्षा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हाथ धर नल से जल की ओर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा जल वितरण की ओर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

वास्तविक समाधान की भागीदारी की होती है कि यहां के प्रभावित जल संरक्षण को अपेक्षा प्राप्त रखने के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। यहां के प्रभावित जल संरक्षण को अपेक्षा प्राप्त रखने के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। जब शहरों में पानी की कमी होती है, तो गर्व और मध्यम वर्षा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हाथ धर नल से जल की ओर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा जल वितरण की ओर योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। यहां पर्यावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है। अजमेर और उदयपुर के लिए एपावरणीय वर्षावरुप से भी खर्च होता है।

जल संकट के लिए एपावरणीय या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह साम

संक्षिप्त

साहबर ठगी का मामला, एक धरा

उदयपुर, (कासं)। साईराबर ठगी जरिये अवैध लेनदेन करने वाले आरोपी को गिरफतार कर जेल भिजवाया। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर प्लूल आकर्त के खिलाफ चलाएं थे जो अधिकार के दौरान जिला पुरकार घटना पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारक उमेश औजा, पुलिस उपाधिकारक कैलाशचंद्र एवं छान उपरोक्त के सुपरविजन में एस्सआई रेजिक्ट घोषित द्वारा किए गए अनुसंधान में मिले साक्षेय के आधार पर प्रतापसिंह बुरु मंत्री सिंह बोगोता निवासी सिद्धि विनायक काम्पलेक्स पार्क सेक्टर 14 गोवर्धन विलास के खिलाफ खातों को बिराए पर देवर साईबर ठगी जरिये लेने देन करने की पुष्ट होने पर एक दिन किया। आरोपी के तीन खातों में ज्यादा लेने देन करने एवं बिशियों के गिरफतार कर ज्यादा लेने में पुलिस ने आरोपी प्रतापसिंह को गिरफतार कर ज्यादा लेने में पेश कर जेल भिजवाया।

अवैध एमडीएम सहित एक पकड़ा

उदयपुर, (कासं)। अवैध एमडीएम सहित एक आरोपी को गिरफतार किया जिला पुरकार घटना के लिए प्रैरित करना, उपर्युक्त एवं सहायक कलेक्टर न्यायालयों में लिंबित नोटिसों के तात्परी, खाते भूमि विभाजन के एवं नामांतरण प्रकरणों के निस्तारण सहित भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16-18 के तहत शुद्धिकरण प्रकरणों का समाधान करने, गैर खातेवारी से खातेवारी प्रकरणों का निस्तारण कर भूमि अधिलेख में इन्ड्राजन सुनिश्चित करने आदि की समीक्षा की।

